सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक: 01 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार 2 फरवरी, 2026
मूल्य ₹ 3/-

शान से सेमीफाइनल में पहुंचा... 7

यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिलकुल नयी सोच की आवश्यकता होगी।

-अल्बर्ट आइंस्टीन

योगी सरकार पर भारी नौकरशाही... 3

आज देश में असमानता ब्रिटिश राज... 2

चीखा विपक्ष, सौतेला बजट

अगर विकास सबका है तो बजट कुछ का ही क्यों?

» मेरे पूरे राजनीतिक करियर का सबसे निराशाजनक केंद्रीय बजट : सिद्धारमैया

» नवीन पटनायक ने केंद्रीय बजट की आलोचना की बोले- ओडिशा को कोई खास फायदा नहीं मिला

» एक्सपर्ट ने माना बजट बाजार को भरोसा तो देता है लेकिन जनता को राहत देने में पीछे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सरकार जिस बजट को विकास का उत्प्रेरक बता रही है वही बजट विपक्ष की नजर में राज्यों के साथ किया गया संस्थागत भेदभाव बनकर उभरा है।

संसद के भीतर तारीफों की तालियां बजीं लेकिन संसद के बाहर राज्यों से उठती आवाजें साफ कह रही हैं कि यह बजट संघीय ढांचे की आत्मा पर चोट है। जिन राज्यों ने देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया है उन्हें या तो नजरअंदाज किया गया या फिर प्रतीकात्मक आश्वासनों के हवाले छोड़ दिया गया है।

विपक्ष ने की कड़े शब्दों में बजट की आलोचना

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेहद संयमित लेकिन तीखे शब्दों में कहा है कि इस केंद्रीय बजट से ओडिशा को कोई ठोस लाभ नहीं मिलने वाला। यह बयान केवल एक राज्य की पीड़ा नहीं बल्कि उस भावना की अभिव्यक्ति है जिसमें गैर भाजपा शासित राज्यों को बार-बार खुद को हाशिये पर खड़ा महसूस होता है। बीजद के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने तो इसे और साफ शब्दों में कहा कि ओडिशा को फिर अनदेखा किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान इस बजट पर सबसे कठोर राजनीतिक टिप्पणी बनकर सामने आया। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मेरे पूरे राजनीतिक करियर का यह सबसे निराशाजनक केंद्रीय बजट है। यह वाक्य केवल नाराजगी नहीं है बल्कि उस निराशा का दस्तावेज है जो दक्षिणी राज्यों में वर्षों से पनप रही है। जहां राजस्व योगदान ज्यादा है और केंद्रीय सहयोग कम।

सरकार ने देश के संकट को नजरअंदाज किया : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-2027 की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत के वास्तविक संकटों को नजरअंदाज करता है और सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता। एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं और घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि किसान संकट में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। किसान संकट में हैं। वैश्विक संकटों का खतरा मंडरा रहा है - इन सब की अनदेखी की जा रही है। एक ऐसा बजट जो सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता, भारत के वास्तविक संकटों को नजरअंदाज करता है। केंद्रीय बजट रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट को फीका बताया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में प्रमुख कार्य क्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन 90 मिनट के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट 2026/27 इसके प्रचार के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से नीरस था। भाषण भी अपारदर्शी था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

उत्साहजनक नहीं है एक्सपर्ट की राय

अर्थशास्त्रियों और औद्योगिक संगठनों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित रही है लेकिन पूरी तरह उत्साहजनक नहीं। सीआईआई और अन्य उद्योग संगठनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर जोर का स्वागत किया है पर साथ ही यह भी माना कि खपत को बढ़ाने के लिए बजट में ठोस कदमों की कमी है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए सीधी राहत के अभाव में आर्थिक मांग को गति देना कठिन होगा। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्योंकि बढ़ता केंद्रीय नियंत्रण संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। औद्योगिक दृष्टि से बजट स्टेबल है लेकिन ब्रेकथ्रू नहीं। एमएसएमई सेक्टर, कृषि आधारित उद्योग और स्टार्टअप्स को लेकर घोषणाएं अपेक्षाकृत सतही मानी जा रही हैं। कुल मिलाकर विशेषज्ञों की राय है कि यह बजट बाजार को भरोसा तो देता है लेकिन जनता को राहत देने में पीछे रह जाता है।

कुछ को ही बजट से लाभ

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भी बजट को अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार किया है। न सिंचाई परियोजनाओं पर ठोस घोषणा न औद्योगिक प्रोत्साहन न ही विशेष वित्तीय सहायता। उन्होंने कहा कि यह बजट तेलंगाना की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। इन बयानों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। यह बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का नक्शा है। और इस नक्शे में कई राज्य कई वर्ग और कई क्षेत्र सिरे से गायब हैं। सरकार विकास सबका का नारा देती है लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर विकास सबका है तो बजट कुछ का ही क्यों?

बंगाल के प्रति भाजपा का सौतेला रवैया : अभिषेक

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने पेश केंद्रीय बजट को चुनावी राज्य बंगाल के प्रति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "सौतेले रवैये" का प्रतिबिंब बताया। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का दावा करते हुए, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि भाजपा "पश्चिम बंगाल की जनता को सबक सिखाने" की कोशिश कर रही है। तृणमूल मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बनर्जी ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, "बंगाल में वे हार रहे हैं। इसलिए भाजपा अपने सौतेले रवैये से लोगों को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है।" लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बनर्जी ने कहा, "लेकिन लोकतंत्र में यह बात उलटी पड़ती है। आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी।

मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बजट सत्र में भाग लेने संसद पहुंचीं और उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्रीय बजट 2026-27 से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। बजट को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन देखते हैं। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक से नहीं हुआ है। तिवारी ने बताया, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक से नहीं हुआ है। निजी पूंजी निवेश में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद ढांचागत असमानताओं को समझेंगे और ईमानदारी से उनका समाधान करेंगे।

कई मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत : बशीर

आईयूएमएल सांसद ई.टी. मोहम्मद बशीर ने कहा कि एमजीएनआरईजीए की दुर्दशा तो सभी जानते हैं। आईयूएमएल सांसद ई.टी. मोहम्मद बशीर ने कहा, यह एक नाजुक मोड़ है। कई मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर भारत की मौजूदा स्थिति में। कई चीजों को गंभीरता से निपटाने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम सभी एमजीएनआरईजीए की दुर्दशा जानते हैं। उन्होंने इसकी पूरी संरचना बदल दी है। यह मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकार द्वारा उठाया गया सबसे क्रांतिकारी कदम था।

विपक्ष के आरोपों को सरकार ने नकारा

सरकार यह भी कहती है कि राज्यों के लिए कर हस्तांतरण और ग्रांट्स की प्रक्रिया पहले से तय फॉर्मूले पर आधारित है न कि राजनीतिक पसंद नापसंद पर। बजट भाषण में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उल्लेख कर सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की कि केंद्र राज्य संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है।

मतदाताओं के नाम चुनिंदा रूप से हटाने की बड़ी साजिश : अखिलेश

» बोले सपा प्रमुख - नाम हटाने में जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया जा रहा है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ईआरओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की

सपा ने चुनाव आयोग से फिर शिकायत की है कि उसके समर्थक वैध मतदाताओं के नाम काटने के लिए भाजपा के नेता फॉर्म-7 भरकर जमा कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने इन मतदाताओं के नाम और एपिक नंबर लिखा प्रिंटेड (छपे-छपाए) फॉर्म तैयार करवाया है। सपा ने वैध मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मसौदा सूची से मतदाता का नाम डिलीट करने से पहले संबंधित वोटर को नोटिस प्राप्त (रिसीव) कराई जाएगी। मतदाता के घर पर नोटिस एक सप्ताह तक चस्पा की जाएगी।'आरओ अपने नोटिस बोर्ड पर एक सप्ताह तक मतदाता का नाम काटने के लिए सूची प्रदर्शित करेंगे और राजनीतिक दलों को मतदाता का नाम काटने संबंधी सूची देनी होगी। पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही मतदाता सूची से नाम डिलीट किए जा सकेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सपा के प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह यादव और राधेश्याम सिंह शामिल रहे।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार व चुनाव आयोग पर एकबार फिर तीखा हमला बोला है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि मतदाताओं के नाम चुनिंदा रूप से हटाने की बड़ी साजिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत विपक्षी वोटों को निशाना बनाया जा रहा है।

एक पोस्ट में उन्होंने गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा, एसआईआर के तहत गांवों में पहले से छपे हुए फॉर्म 7 को कौन बांट रहा है (जिसके जरिए कोई आपत्ति दर्ज कराकर किसी दूसरे का नाम मतदाता सूची से हटवाने की साजिश रच सकता है) ? उन्होंने दावा किया कि फॉर्म में सूचीबद्ध शिकायतकर्ताओं की कोई पहचान या ठिकाना ज्ञात नहीं है और नाम हटाने में जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

यादव के अनुसार, इस कथित प्रक्रि या से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) समुदायों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के मतदाताओं पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के बिना ही बड़े पैमाने पर उनके नाम हटाए जा रहे थे, जबकि उनके दस्तावेज़ पूर्ण और सही थे।

उन्होंने लिखा, जिस व्यक्ति के नाम पर आपत्ति जताई जा रही है, उसे भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि सब कुछ सही होने के बावजूद उसका नाम हटाया जा रहा है। मीडिया से अपील करते हुए यादव ने समाचार चैनलों, अखबारों, स्थानीय यूट्यूबरों और जमीनी स्तर के पत्रकारों से लोकतंत्र के हित में इस मेगा-घोटाले की जांच और पर्दाफाश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के हित में, हम स्थानीय यूट्यूबर और स्थानीय समाचारकर्मी आपसे इस मेगा-घोटाले का पर्दाफाश करने और इसे अपने स्तर पर प्रकाशित या प्रसारित करने की मांग करते हैं। हम आपको पूरे देश और राज्य के सामने लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता सच्चे दर्शकों और पाठकों तक पहुंचे।

पाकिस्तान ने खेलमंत्री व बीसीसीआई को मारा तमाचा : प्रियंका चतुर्वेदी

» टी-20 वर्ल्डकप में भारत संग नहीं खेलने को लेकर विपक्ष का सरकार परह हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला लिया है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। इस पर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान पर तंज कसा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, अच्छा हुआ जो बीसीसीआई नहीं कर पाया, वो अब आतंकिस्तान टीम कर रही है? आईसीसी को अब उन पर जुर्माना लगाना चाहिए ताकि जुर्माना चुकाने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़े।

प्रियंका के कहने का मतलब था कि बीसीसीआई जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच रद्द करवाना मजबूत कदम नहीं उठा पाया, वो काम अब पाकिस्तान की टीम खुद कर रही है। यानी भारत से मैच से भाग रही है, प्रियंका ने आतंकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करके तीखी खिल्ली उड़ाई और आईसीसी से पाकिस्तान पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की, ताकि उन्हें आर्थिक दबाव महसूस हो।

केंद्र ने आदिवासियों को हाशिये पर धकेल दिया : हेमंत सोरेन

» बोले झारखंड सीएम- असम में सत्ता में बैठे व्यापारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र और असम में सत्ता में बैठे लोगों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि व्यापारी हैं और आदिवासी समुदाय को हाशिये पर धकेलकर केवल संसाधनों के दोहन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। असम के तिनसुकिया में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि चुनावी राज्य असम में चाय जनजातियों को राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने के बावजूद उपेक्षित किया जा रहा है।

सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संबोधन का हवाला देते हुए लिखा, देश और असम में सत्ता में बैठे लोग राजनीतिज्ञ नहीं, व्यापारी हैं। वे सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। ऐसे में आदिवासियों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज आत्मसम्मान के साथ जीने वाला समाज है और आंखों में आंखें डालकर चलने में विश्वास रखता है। सोरेन ने कहा, इन्हीं लोगों (केंद्र और असम में सत्ता में बैठे लोग) ने मुझे जेल भेजा था। मैंने तब कहा था कि अगर मैं आगे आया, तो उनकी गले की हड्डी बनूंगा।

भाजपा विधायक के रिश्तेदार ने की खुदकुशी

प्रॉपर्टी के काम में पार्टनर्स पर धोखाधड़ी का आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के रिश्तेदार शिवम त्रिपाठी ने खुदकुशी कर ली। विनय रिश्ते में शिवम के फूफा लगते हैं। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े शिवम के परिजनों का आरोप है कि बिजनेस में पार्टनर द्वारा पैसे हड़पने और मानसिक प्रताड़ना के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से बलरामपुर निवासी शिवम त्रिपाठी रिश्ता मैनहैटन अपार्टमेंट के टावर ए-2 (फ्लैट नं. 407) में रहते थे। रविवार शाम जब मकान मालिक किसी काम से वहां पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। अंदर शिवम का शव फंदे से लटक रहा था। मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिजनों के अनुसार, शिवम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। आरोप है कि उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने पैसों के लेनदेन में बड़ा घपला किया था। शिवम लंबे समय से उनसे अपना बकाया मांग रहे थे, लेकिन पार्टनर्स न तो पैसे दे रहे थे और न ही सही जवाब। इसी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण शिवम डिप्रेशन में थे।

शिवम के फूफा विनय कुमार त्रिवेदी गोंडा की मेहनौन विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा विधायक हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी राजनीति में सक्रिय हैं और एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं। शिवम के परिवार में उनके पिता राजेश त्रिपाठी, मां और दो छोटे भाई प्रखर व अभिषेक हैं। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।

देश की बेइज्जती कर रहे हैं : इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इंडिया की क्रि केट टीम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि यह बेशर्म लोग हैं यह बेइज्जती कर रहे हैं देश की, हमने तो पुलवामा अटैक के समय भी कहा था, उनके साथ नहीं खेलना है फिर भी इन्होंने जाकर पाकिस्तान के साथ मैच खेला। वहीं उन्होंने आईसीसी के एक्शन पर कहा कि मुझे आईसीसी से कोई मतलब नहीं है मुझे देश से मतलब है, देश का सम्मान है तो मान है, देश का अपमान है तो कुछ नहीं। इससे पहले इमरान मसूद ने कहा कि हिंदुस्तान को ही खेलने की उनके साथ जरूरत क्यों है। अब ये तो बीसीसीआई को सोचना चाहिए ना कि देश के सम्मान के साथ समझौता ना करें बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लिया तो हंगामा था अब ये पाकिस्तान के साथ क्या है?।

पाकिस्तानी धूर्त लोग हैं

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? हमें तो नहीं खेलना चाहिए, हमने तो पहले दिन मना करा था तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। पाकिस्तानी धूर्त लोग हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए. जब उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए अब इंडिया को आपके हिसाब से तो उन्होंने कहा कि पहले मना करना चाहिए था, हमें पहले ही कह देना चाहिए क्लियर एकदम।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

सीएम सुक्खू ने किया होम स्टे पोर्टल का शुभारंभ

» कहा-फायर एनओसी के नाम पर नहीं रुकेगा होटल का नवीनीकरण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां होम स्टे पोर्टल http://homestay.hp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होम स्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यन्त सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होम स्टे संचालकों और होटल मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उनके व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि आपत्ति के नाम पर होटल कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

अतिथ्य उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के कारण होम स्टे के पंजीकरण के रिन्यूअल को रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को ऐसे होटलों को प्रोविजनल पंजीकरण प्रदान करने को कहा, ताकि उनका व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होता रहे। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन से स्वरोजगार अर्जित करने के लिए होम स्टे योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा पर्यटकों को अनछुए पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व में भी पर्यटन क्षेत्र का अधिक योगदान है।

इसलिए वर्तमान सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा कर इसमें शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया है ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

योगी सरकार पर भारी नौकरशाही का तंत्र!

प्रदेश में मृतक आश्रित नियुक्ति में हो रहा गोरखधंधा

» नगर निगमों में ज्यादा आ रही हैं शिकायतें

» शासन के आदेशों एवं नियमों के विपरीत काम

» भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लग रही चपत

मों. शारिक/4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में लगभग 9 साल से भाजपा की योगी सरकार है। सीएम योगी का मानना है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। पर पूरे प्रदेश में मंत्री से लेकर अधिकारी तक उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य के हर नगरनिगम व पालिका में नियुक्ति, विकास व सफाई सबमें धांधली की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात की इस तरह की भी बातें सामने आ रहीं हैं जिसमें जांच हुई कार्रवाई के आदेश हुए पर धांधली जस की तस बनी हुई है।

ऐसा ही एक मामला लखनऊ में एक कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर सामने आया है। गत 14 जून 2022 को तत्कालीन महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार वर्मा ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जिसमें वित्त अधिकारी लेखा अधिकारी और जलकल के अधिकारी ने जांच की थी। जिसमें 13 दिसंबर 2022 को नगर निगम लखनऊ द्वारा नियुक्ति की जांच हेतु मूल सर्विस पत्रावली मंगाई गई थी। उसमें 27 फरवरी 2023 को लखनऊ नगर निगम द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति को शासन के आदेशों एवं नियमों के विपरीत दर्शाया गया।

मृतक आश्रित नियुक्ति को गलत बताया

लखनऊ नगर निगम द्वारा जांच आख्या जलकल विभाग में भेजने के बाद तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक राम कैलाश द्वारा पुनः चार सदस्य जांच कमेटी का गठन करते हुए मृतक आश्रित नियुक्ति को गलत ठहराया। 12 मई 2023 को तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक राम कैलाश द्वारा अपने कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया कि 15 दिवसों में कार्यवाही की जाएगी। 24 मई 2023 को हजरतगंज कोतवाली द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति को गलत बताते हुए वर्ष 2009 में नियुक्ति से पूर्व लड़की छेड़खानी मामले की चिनहट कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत होने की भी पुष्टि की। 25 मई 2023 को हजरतगंज सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी)द्वारा भी मृतक आश्रित नियुक्ति को गलत बताते हुए वर्ष 2009 में नियुक्ति से पूर्व लड़की छेड़खानी मामले की चिनहट कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत होने की भी पुष्टि की इस तरह हुई मृतक आश्रित कोटे में अवैध नियुक्ति जलकल विभाग में कार्यरत स्वर्गीय रामाश्रय राम के देहांत के फल स्वरुप उनके पुत्र मृत्युंजय को कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर भर्ती दी गई।

समुचित अहर्ता ना होने पर की गई नियुक्ति

मृत्युंजय कि मृतक आश्रित में समुचित अहर्ता ना होने पर की गई नियुक्ति की जांच के संदर्भ में नगर निगम लखनऊ में गठित चार सदस्य जांच समिति द्वारा जांच की गई । नगर निगम लखनऊ द्वारा 27 फरवरी 2023 को जलकल विभाग को अवगत कराया की सचिव उत्तर प्रदेश शासन वेतन आयोग अनुभाग दो के द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2001 द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद को मृत्यु घोषित कर दिया गया था। लखनऊ नगर निगम ने अपनी आख्या में साफ दर्शाया की श्री मृत्युंजय की कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर पुनरिचित वेतन बैंड रुपए 5200 –20200 ग्रेड पे 1900 पर की गई मृतक आश्रित नियुक्ति को शासन के आदेशों एवं नियमों के विपरीत की गई है।

गलत तरीके से प्रमोशन

वही महाप्रबंधक जलकल की स्वीकृति 31 जनवरी 2017 के अनुसार सचिव कार्यालय आदेश संख्या 1472 सचिन दिनांक 29 जनवरी 2014 के अनुसार 1 जनवरी 2006 अथवा उसके उपरांत सीधी भर्ती के कार्मिकों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या 13 18 दिनांक 8 दिसंबर 2008 के अनुसार वेतन निर्धारण भी कर दिया शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए। कनिष्ठ लेखा लिपिक पद पर नियुक्ति करने से पूर्व ही कनिष्ठ लेखा लिपिक पद मृत्यु संवर्ग होने की जलकल विभाग को जानकारी थी । 24 सितंबर 2001 वित्त विभाग वेतन आयोग अनुभाग दो द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक पद को मृत्यु संवर्ग घोषित करते हुए कनिष्ठ लेखा लिपिक पद को सहायक लेखाकार पदों में सम्मिलित किया जा चुका था।

सीधी भर्ती का लाभ देने का आरोप

जलकल विभाग द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर पद नामित करने के साथ ही अवैध मृतक आश्रित नियुक्त कर्मी मृत्युंजय सहायक लेखाकार को गलत तरीके से सीधी भर्ती का लाभ देते हुए सीधी भर्ती का दर्जा भी दे दिया गया। कई शिकायतें होने के बाद अवैध नियुक्ति की जांच के लिए प्रभारी अधिकारी नगर निगम लखनऊ में दिनांक 13 दिसंबर 2022 को श्री मृत्युंजय सहायक लेखाकार की व्यक्तिगत पत्रावली व सेवा पुस्तिका नियुक्ति जांच हेतु उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया था । प्रभारी अधिकारी नगर निगम लखनऊ द्वारा अनुरोध करने के पश्चात

मृत्युंजय, आश्रित नियुक्त कर्मी

जलकल विभाग सचिव द्वारा 20 दिसंबर 2022 को मृत्युंजय सहायक लेखाकार की व्यक्तिगत पत्रावली व सेवा पुस्तिका जांच हेतु प्रभारी अधिकारी नगर निगम लखनऊ को उपलब्ध कराई थी।

सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं

मृत्युंजय की नियुक्ति करने से 2 महीने पहले 10 अक्टूबर 2011 वित्त विभाग वेतन आयोग अनुभाग दो द्वारा पुनः पूर्व आदेश को जारी किया गया। वही इसे जारी करने के साथ ही वित्त विभाग ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों स्वदेशी संस्थाओं सार्वजनिक उपक्र मों निगम स्थानीय निकायों जल संस्थानो तथा विकास प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उक्त लेखा संवर्ग पदों पर भर्तियां कभी भी न की जाए। जबकि मृत्युंजय के नियुक्ति कार्यालय आदेश सचिव द्वारा साफ लिखा गया है कि भविष्य में यदि उत्तराधिकार के संबंध में कोई बाद विवाद उत्पन्न होता है या पुलिस सत्यापन में चरित्र संदिग्ध पाया जाता है तो विभाग द्वारा नियमानुसार तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

दो बार कराई भर्ती

भर्ती के समय मृत्युंजय की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट साइंस एवं बीकॉम द्वितीय वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे । जलकल विभाग सचिव द्वारा 31 दिसंबर 2011 को कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई जिसके अनुपालन में मृत्युंजय द्वारा 7 जनवरी 2012 को योगदान आख्या प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण किया गया। वही सेवा पत्रावली के अनुसार मृत्युंजय

द्वारा दो बार कार्यभार ग्रहण किया गया है जिसकी तिथियां 16 जनवरी 2012 एवं 17 जनवरी 2012 है। वही नियुक्ति के पश्चात 4 मई 2022 को जलकल विभाग में चयन समिति की संस्कृति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रम में जलकल विभाग में कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मियों को सहायक लेखाकार के पद पर पद नामित किया गया।

गलत तरीके से वेतनमान में भी हुई बढ़ोतरी

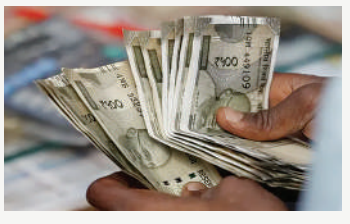

इतना ही नहीं मृत्युंजय की नियुक्ति के बाद जलकल विभाग अधिकारियों ने गलत तरीके से वेतनमान में भी हुई कई बार बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2012 से वर्ष 2022 तक अर्थात 10 वर्षों में लगातार तीन बार बढ़ाया गया ग्रेड पे 17 जनवरी 2012 को नियुक्ति के समय ग्रेड पे 1900 था ठीक 1 वर्ष बाद दिनांक 31 मई 2013 को मृत्युंजय का ग्रेड पे 2000 कर दिया गया। जो की निर्माता शासन के आदेशों के विपरीत है अर्थात गलत तरीके से व्यक्तिगत लाभ विभाग द्वारा मृत्युंजय को पहुंचाया गया है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

अब प्रशासनिक जवाबदेही तय करना जरूरी

देश के हर राज्य में प्रशासनिक लापरवाही की खबरें सामने आती रहती है। चाहे वह कोई हादसा हो या सरकारी काम करने का तरीका। पर जब घटनाएं सामने आतीं है तो खूब शोर-शराबा होता है पर काम करने का तरीका नहीं बदलता है। भारत की कार्य संस्कृति में सुधार के लिए लोकसेवा से जुड़े प्रत्येक कर्मी को उसे दिए गए काम को पूरी ईमानदारी के साथ निर्धारित समय से पहले पूरा करना चाहिए। साथ ही सभी कर्मियों पर काम का समान बोझ डालने, समान सुविधाएं देने, प्रतिभावान कर्मियों को पुरस्कृत करने तथा पदोन्नति के लिए एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कर्मियों को सामान्य वर्ग के कर्मियों से पहले पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। कार्य संस्कृति एक सतत् प्रक्रिया है जिसके निरन्तर प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है। कर्मचारियों के कार्यकाल और उनके जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए भी खास ध्यान देना चाहिए और उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। भारत की कार्य संस्कृति में सुधार का उद्देश्य टॉक्सिक कार्यस्थल संस्कृति को कम करना और उत्पादकता बढ़ाना है।

कार्य-जीवन संतुलन और कर्मचारियों के लिए लचीले काम के घंटे और रिमोट वर्किंग विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। मानसिक तनाव को कम करने के लिए समय-समय पर ब्रेक और छुट्टियां सुनिश्चित करना और काम के बाद के घंटों में काम के ईमेल या कॉल से बचना चाहिए। नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए ओपन-डोर पॉलिसी अपनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना आवश्यक है। नई तकनीकें और कौशल सीखने के लिए समय और संसाधन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। भारत की कार्य-संस्कृति में सुधार आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। अक्सर देखा जाता है कि काम के घंटों की संख्या को ही मेहनत का पैमाना मान लिया जाता है, जबकि वास्तविक प्रगति परिणामों से मापी जानी चाहिए। एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति वही होती है, जहां समय की कद्र, अनुशासन और आपसी सम्मान को प्राथमिकता मिले। कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देना, उनकी बात सुनना और योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का रास्ता देना संस्थानों को मजबूत बनाता है।कंपनियों व नियोक्ताओं को काम की गुणवत्ता को मापने की संस्कृति अपनाने पर ही फोकस करना चाहिए। घंटों के बजाय परिणाम आधारित मूल्यांकन करने, सीमाओं का सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता तथा वैश्विक स्तर पर विकास में अग्रणी आने का ध्येय रख काम के घंटों और जीवन संतुलन बनाए रखने के प्रयास जरूरी हैं। समावेशी सहानुभूति पूर्ण स्थल देश के आर्थिक विकास और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दे सकेगा।

सभी कर्मियों पर काम का समान बोझ डालने, समान सुविधाएं देने, प्रतिभावान कर्मियों को पुरस्कृत करने तथा पदोन्नति के लिए एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कर्मियों को सामान्य वर्ग के कर्मियों से पहले पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

श्रमिक-किसान कल्याण हो जीडीपी का पैमाना

अरुण मारिया

भारत के नीति-निर्माता दुविधा में हैं। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में जरूरत से बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, जिसको इसमें कार्यरत लोगों की संख्या के हिसाब से मापा जाता है, वह बहुत कम है। उनका मानना है कि ज्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण इलाकों एवं खेतों से और लघु, 'अनौपचारिक' कारखानों और सेवा उद्यमों से भी निकालकर शहरों में लाया जाए ताकि उन्हें बड़े, 'औपचारिक' कारखानों एवं सेवा उद्यमों में काम पर लगाया जा सके। समस्या यह है कि बड़े औपचारिक उद्यम पर्याप्त सुरक्षित नौकरियां और अच्छा वेतन नहीं दे रहे हैं। वे ज़्यादा लोगों को काम पर रखने, उन्हें अधिक तनख्वाह और सामाजिक सुरक्षा देने को तैयार नहीं हैं।

इसकी बजाय, वे वेतन की लागत कम रखने के लिए अधिक 'लचीले' श्रम कानूनों की मांग कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या यह है कि सभी क्षेत्रों मसलन, विनिर्माण, सेवाएं और कृषि में नियोक्ता अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंसानों के बजाय ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस मुख्य सुधार की ज़रूरत है, वह है व्यावसायिक उद्यम के ढर्रे और प्रचालन में सुधार। मजदूर, चाहे वे खेतों में हों या कारखानों में, वे जिस उद्यमों में काम करते हैं उनके मालिकों की सोच होती है, उनके काम से हुआ मुनाफा, उनका ही रहे और उनकी संपत्ति में इजाफा करे, न कि यह लाभ किसी वित्तीय निवेशक की संपत्ति बढ़ाने के काम आए। उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक पूंजीगत संपत्ति जैसे कि विनिर्माण उद्यम में मशीनें और खेती के लिए ज़मीन, उद्यम में काम करने वाले मज़दूरों की होनी चाहिए। मजदूर अपने मालिक खुद हों और उन्हें स्टॉक मार्केट निवेशकों और सामंती जमींदारों की मल्कियत वाले कारखानों और खेतों में कर्मचारी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। काम से होने वाले मुनाफ़े का इस्तेमाल वह कैसे करेंगे, यह चुनने का अधिकार उन्हें होना चाहिए।

अब चाहे तो अपने उद्यम में और अधिक निवेश करें या अपने परिवार के कल्याण और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं। जैसा कि माइक बर्ड ने अपनी किताब 'द लैंड ट्रैप, ए न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एसेट' नामक पुस्तक में बताया है कि भू-स्वामित्व में सुधार, जिसके तहत जमीनें जमींदारों से लेकर उनके खेतों में काम करने वाले

मजदूरों को हस्तांतरित की गई, उसकी बदौलत पिछले 50 सालों में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में छोटे किसानों की आय भारत की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। बर्ड व्याख्या करते हैं कि भारत की तुलना में अन्य देशों में सुधार तेज़ी से क्यों हुए। सभी देशों में निहित स्वार्थ सुधारों के रास्ते में आड़े आते हैं। हालांकि, उन देशों के नेताओं ने किसान-मजदूरों के अधिकारों का समर्थन किया, न कि पूंजीपति-मालिकों का। सुधारों से छोटे किसानों की कमाई और संपत्ति बढ़ी, और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा निवेश किया। लोगों को खेती से हटाए बिना भी, कृषि-उत्पादन और कृषि उत्पादकता बढ़ी है। अर्थशास्त्रियों और व्यापार करने वालों को उद्यमों में 'पैमाने' पर फिर से सोचना चाहिए। एक मानकीकृत वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन, फैक्टरी उत्पादन बढ़ाने में सहायक कोई प्रक्रिया हो या बड़े खेत में एक ही फसल उगाना, बड़ी मशीनों का उपयोग और दोहराव वाले कामों को करने के लिए कम कुशल श्रमिकों को रोजगार देकर अपनी आर्थिक दक्षता बढ़ाता है। बड़े पैमाने के उद्यमी मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूंजी लगाने की हैसियत रखते हैं। इस तरह, उन्हें कम श्रमिक और बुद्धि की जरूरत पड़ती है। ऐसा करके जहां उनकी दक्षता और उत्पादन मात्रा बढ़ सकती है, और उत्पादकता भी। ऐसे उद्यम कम श्रमिकों को नौकरी पर रखते हैं। वे अर्थव्यवस्था के 'रोजगार रहित' सकल घरेलू उत्पाद बढ़ोतरी से योगदान करते हैं। छोटे खेत जो जैविक तरीके से उन्नत किस्म की फसलें उगाते हैं, उन खेतों में उत्पादन की 'संभावना' ज्यादा होती है। कचरा खेत में अपने आप उपयोगी अवयव बन जाता है, खेतों में जहां पर जानवर भी रखे होते हैं।

संभावना वाले खेत स्वाभाविक रूप से अधिक टिकाऊ होते हैं। ऐसे छोटे खेतों में, जिनका पैमाना कम किंतु संभावना अधिक हो, सामग्री और ऊर्जा अपने भीतर और ऐसे छोटे खेतों के आसपास ही घूमती रहती है। पर्यावरण वैज्ञानिक वैक्लाव स्मिल ने आधुनिक उद्योगों, खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों, और वैश्विक परिवहन प्रणालियों में हाइड्रोकार्बन ऊर्जा और अन्य गैर-नवीकरणीय अवयवों की सकल व्यवस्थात्मक जरूरतों की गणना की है। अपनी किताब, हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स में, वह समझाते हैं कि आधुनिक एवं सघन तकनीकी विधि से बड़े पैमाने का खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली मिट्टी, पानी और वातावरण का सबसे बड़ा प्रदूषक है।

अदालती चौखट पर नूरा-कुश्ती की हकीकत

डॉ. सुधीर कुमार

न्यायपालिका वह पवित्र स्थान है जहां सत्य की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन आज 'कलूसिव सूट' (साजिशी मुकदमों) के जरिए इस मंदिर की गरिमा को चुनौती दी जा रही है। यह कानूनी जगत का वह अंधेरा कोना है जहां वादी और प्रतिवादी विरोधी होने का मात्र ढोंग करते हैं, जबकि हकीकत में वे एक ही 'साजिशी पटकथा' के किरदार होते हैं। जब न्याय की गुहार लगाने वाला और उसका विरोध करने वाला, दोनों ही परदे के पीछे एक हो जाएं, तो अदालत का कठघरा केवल एक रंगमंच बनकर रह जाता है। न्याय की बुनियादी अवधारणा को ठेस पहुंचती है। ऐसी कृत्रिम लड़ाइयां न केवल न्यायिक समय की बर्बादी हैं, बल्कि उन वास्तविक शोषितों का हक भी मारती हैं जो न्याय की कतार में अंतिम पायदान पर खड़े हैं।

सरल शब्दों में कहें तो जब दो पक्ष आपस में हाथ मिलाकर अदालत के सामने 'नूरा-कुश्ती' (दिखावटी लड़ाई) करते हैं, तो उसे कानून में 'कलूसिव सूट' कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे 'साजिशी मुकदमा' कहना ज्यादा सटीक होगा। यह एक ऐसा कृत्रिम विवाद है जहां दोनों पक्ष वास्तव में एक-दूसरे के विरोधी नहीं होते और उनके बीच कोई वास्तविक कानूनी संघर्ष नहीं होता। वे अदालत की चौखट पर सिर्फ इसलिए पेश होते हैं ताकि आपसी साजिश के जरिए एक ऐसी 'डिक्री' या सरकारी आदेश हासिल कर सकें, जिसे वे ईमानदारी के रास्ते से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमारी भारतीय न्याय प्रणाली 'प्रतिद्वंद्वी पद्धति' पर आधारित है, जिसका मूल सिद्धांत ही यह है कि जब दो विरोधी पक्ष पूरी शिद्दत से अपनी बात और दलीलें रखेंगे, तभी सत्य छनकर बाहर आएगा। लेकिन जब विरोध ही दिखावटी हो और दोनों पक्ष 'मेज के नीचे' हाथ मिला चुके हों, तो अदालत महज एक मूकदर्शक बनकर रह जाती है। निस्संदेह, यह उस पवित्र तंत्र की तौहीन भी है जिसे समाज में न्याय की रक्षा के लिए बनाया गया है। कानून की नजर में 'मिलीभगत' के लिए कोई सहानुभूति नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 40 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि कोई फैसला, आदेश या डिक्री 'धोखे' या 'मिलीभगत' से प्राप्त की गई है, तो उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। यह धारा एक सुरक्षा कवच है। इसके अलावा, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत अदालतों को यह अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है कि वे ऐसे मुकदमों को पहचानते ही खारिज कर दें। कानून का एक वैश्विक सिद्धांत है- धोखे से कभी भी कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं हो सकता। भारतीय न्यायपालिका ने हमेशा से इन साजिशी मुकदमों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। इस दिशा में 'नगुबाई अम्मल बनाम बी. शमा राव' (1956) का फैसला एक नजीर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 'साजिश' और 'धोखे' के बीच के महीन अंतर को स्पष्ट किया। अदालत के अनुसार, 'फ्रॉड' में एक पक्ष दूसरे को छलता है, किंतु 'कलूजन' में दोनों पक्ष मिलकर अदालत के साथ छल करते हैं।

जब वादी और प्रतिवादी के बीच कोई वास्तविक विवाद न हो और उनका एकमात्र उद्देश्य न्याय की आड़ में किसी तीसरे पक्ष का हक मारना हो, तो वह पूरी तरह 'साजिश' है। इसी प्रकार, 'रूपचंद गुप्ता बनाम रघुवंश कुमार' (1964) में अदालत ने आगाह किया कि यदि डिक्री का उद्देश्य किसी किराएदार या हकदार का अधिकार मारना है, तो वह डिक्री बातिल (शून्य) होगी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि न्याय के सिंहासन पर बैठी अदालतें केवल कागजी सबूतों को नहीं तौलतीं, बल्कि मुकदमों के पीछे छिपी बदनियती को पहचानने की कुव्वत भी रखती हैं। लोग ऐसा जोखिम अक्सर निजी स्वार्थ के लिए उठाते हैं, जैसे टैक्स चोरी, बैंक के कर्ज से बचना या अवैध कब्जा करना। इसका सबसे बड़ा खमियाजा उस 'तीसरे पक्ष' को भुगतना पड़ता है जो अनजाने में अपना कानूनी हक खो देता है; जैसे पिता-पुत्र की मिलीभगत बैंक के अधिकार को खत्म कर सकती है। यहां 'मैत्रीपूर्ण मुकदमे' (धारा 90, नागरिक प्रक्रिया संहिता) और 'साजिशी मुकदमे' के बीच की 'कुत्सित मंशा' को समझना लाजिमी है। जहां मैत्रीपूर्ण वाद कानूनी स्पष्टता के लिए होते हैं, वहीं साजिशी मुकदमे का उद्देश्य 'अधिकार का अपहरण' करना होता है। इसी महीन लकीर को पहचानना ही एक न्यायाधीश की असल परीक्षा है। एक वकील के लिए उसका पेशा केवल जीविका नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। वकीलों को यह समझना होगा कि वे 'ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' हैं, न कि किसी साजिश के पटकथा लेखक।

यदि कोई अधिवक्ता जानते हुए भी ऐसे फर्जी मुकदमों का हिस्सा बनता है, तो बार काउंसिल को ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस खतरे को टालने के लिए सजग 'न्यायिक सक्रियता' अनिवार्य है। अदालतों को मुकदमों के पीछे छिपी मंशा को भांपना होगा; जहां प्रतिवादी बिना किसी प्रतिरोध के सब स्वीकार कर ले, वहां न्यायपीठ को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारी आर्थिक दंड की ऐसी नजीर पेश करनी होगी, जो भविष्य के लिए सबक बने। साथ ही, उन 'तीसरे पक्षों' के लिए कानूनी राह आसान करनी होगी, जो इन बंद कमरों की साजिशों के असली शिकार होते हैं। न्यायपालिका की वास्तविक ताकत उसकी पारदर्शिता और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा में निहित है। हमें एक ऐसी न्यायिक संस्कृति विकसित करनी होगी जहां चालाकी की जगह सच्चाई का बोलबाला हो। जैसा कि कहा गया है, 'न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए'। जब हम इन साजिशी मुकदमों का पर्दाफाश करेंगे, तभी हम एक पारदर्शी-मजबूत न्याय प्रणाली का निर्माण कर पाएंगे।

भुजंगासन

भुजंगासन से पीठ मजबूत होती है और पेट का तनाव कम होता है। यह पेट की चर्बी कम करने में बेहद प्रभावी आसन है। साथ ही कमर और स्पाइन के लिए शक्तिशाली भी है। अभ्यास के लिए पेट के बल लेटें, हथेलियों को कंधों के नीचे रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि अभ्यास के दौरान कमर पर झटका न दें, शरीर को सिर्फ उतना ही उठाएं जितना आराम से हो। किडनी से जुड़ी समस्याएं खानपान और लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकती हैं। किडनी की पथरी की समस्या में भुजंगासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका नियमित रूप से अभ्यास करने से किडनी पर जोर पड़ता है और इससे किडनी में मौजूद विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी फायदा मिलता है।

पवनमुक्तासन

यह आसन पाचन के लिए रामबाण है। गैस, ब्लोटिंग और कब्ज घटाता है और पेट की अंदरूनी चर्बी पर सीधा असर डालता है। इसके अभ्यास के लिए पीठ के बल लेटें, घुटनों को मोड़कर सीने से लगाएं, हाथों से पकड़कर 20-30 सेकंड तक गहरी सांस लें। पवनमुक्तासन का अभ्यास पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। और अगर पाचन सही रहता है तो चर्बी का जमाव कम होता है। इसके अलावा कमर दर्द, साइटिका, हृदय रोग, गठिया में भी यह आसन लाभकारी है। स्त्रियों के लिए गर्भाशय सम्बन्धी रोग में पावनमुक्तासन काफी फायदेमंद है। इस आसन से मेरूदंड और कमर के नीचे के हिस्से में मौजूद तनाव दूर होता है। पवनमुक्तासन करने में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए।

घर पर इन योगासनों के करने से घटेगी पेट की चर्बी

पेट की चर्बी बेहद जिद्दी होती है। ये एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेती। भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कामकाज और थकान के बीच भारी-भरकम वर्कआउट कर पाना आसान नहीं होता है। लोगों का मानना है कि अगर पेट कम करना है तो पसीना बहाना होगा, हालांकि ये सभी मामलों में सच नहीं है। पेट की चर्बी कोई रातों-रात नहीं बढ़ती और न ही रातों-रात घटती है। लेकिन कुछ सरल योगासनों को अपनाकर पेट की चर्बी को पिघलाया जा सकता है। कुछ आसन पाचन में सुधार लाते हैं और शरीर को हल्का महसूस कराने में सहायक है। जिनके रोजाना 15 से 20 मिनट अभ्यास से पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है, वो भी ज्यादा मेहनत या भारीभरकम वर्कआउट किए। आप सुबह खाली पेट 10-15 मिनट रोजाना अभ्यास करें। नए योगी हैं तो हर आसन 20-30 सेकंड तक करें। लगातार अभ्यास करने से तीन से चार हफ्तों में फर्क दिखने लगता है।

मार्जरी आसन

इस आसन को पोज कैट यानी बिल्ली और दूसरी बार काओ यानी गाय जैसी बनती है। इसलिए इसे कैट ऐंड काओ आसन कहते हैं। हिंदी में इसे मार्जरी आसन कहते हैं। इस आसन से रीढ़ लचीली होती है और पूरा शरीर रिलैक्स होता है। नियमित अभ्यास से पेट को अंदर खींचने की क्षमता बढ़ती है। यह आसन स्ट्रेस कम करता है, जो कि पेट की चर्बी का बड़ा कारण है। मार्जरी आसन के नियमित अभ्यास के लिए दोनों हाथों और घुटनों के बल शरीर को गाय की आकृति में लाएं। सांस भरते हुए सिर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर उठाएं।

ताड़ासन

ताड़ासन योगासन की दुनिया का मूल स्वर है। इससे रीढ़ एक सीधी रेखा में आती है। पेट के आसपास की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आता है और शरीर के संतुलन में सुधार होता है। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं। फिर हाथ ऊपर उठाएं, उंगलियां जोड़ें और पूरा शरीर आसमान की ओर खींचें। 30-40 सेकंड इसी स्थिति में रहें। इससे कोर मसल्स एक्टिव होती हैं, शरीर की मुद्रा सुधरती है और पेट का फैलाव कम होता है। यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। मांसपेशियों और स्नायु बंधों में खिंचाव उत्पन्न होने से बढ़ती हुई अस्थियां लंबी होती हैं, जिससे शरीर की लंबाई बढ़ती है। इसके अलावा, ताड़ासन मलाशय और आमाशय की मांसपेशियों और आंतों में खिंचाव उत्पन्न करता है, इसलिए प्रेगनेंसी के 6 माह तक उदर की मांसपेशियों और स्नायुओं को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोगी होता है।

हंसना मना है

लड़का-डार्लिंग तुम कहां थी, मैं कल से तुम्हारा फोन लगा रहा हूं, लड़की- सॉरी बेबी, मैं फ्रेंड के साथ मॉल में गयी थी, बहुत सारा सामान खरीदा, लड़का-वाओ, क्या क्या लिया? लड़की-ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 ब्रेसलेट, 1 रुमाल और 300 सेल्फी।

प्रेमिका (प्रेमी से)- क्या शादी के बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करोगे? प्रेमी (प्रेमिका से)- क्यों नहीं? मुझे तो शादीशुदा लड़कियां बहुत पसंद है।

प्रेमिका- तुम तो बस काम में लगे रहते हो! मेरी तो परवाह ही नहीं करते! प्रेमी- एक बात तुम गौर से सुन लो! प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते!

प्रेमी - डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा बोला- हमारी गाय नहीं मिल रही! दिखे तो बताना।

पत्नी ने डॉक्टर से कहा- डॉक्टर साहब ! मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा- इसका कोई इलाज नहीं हैं। पत्नी बोली- कम से कम ऐसी कोई दवा तो उनको दीजिए जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं।

कहानी | शहरी चूहा और गांव का चूहा

दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक शहर में रहता था और दूसरा गांव में, लेकिन दोनों एक-दूसरे की खबर वहां आने-जाने वाले चूहों से लेते रहते थे। एक दिन शहर के चूहे ने गांव आने की बात दोस्त तक पहुंचा दी। गांव का चूहा खबर सुनकर काफी खुश हुआ। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशी से किया। गांव के चूहे ने कहा 'शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा न, लेकिन यहां गांव का वातावरण काफी शुद्ध है।' फिर गांव के चूहे ने बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल-चावल परोसे। दोनों ने खूब मजे से खाने का आनंद लिया। फिर दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। गांव की हरियाली दिखाते वक्त गांव के चूहे ने पूछा, 'क्या शहर में भी ऐसे ही हरे-भरे नजारे हैं?' शहर के चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शहर आने का निमंत्रण जरूर दिया। रात में दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। सुबह चूहे ने नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोसे। ये देखकर शहर का चूहा चिढ़ गया। उसने कहा, 'तुम्हारे यहां क्या हर रोज हर वक्त एक ही खाना खाया जाता है? क्या इन सबके अलावा कुछ और खाना नहीं है?' शहर के चूहे ने कहा 'चलो इसी वक्त शहर चलते हैं। वहां देखना कितनी आराम की जिंदगी है और कितने प्रकार की चीजें खाने के लिए हैं।' दोनों ही चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। शहर का चूहा एक बड़े से घर के बिल में रहता था। उतना बड़ा घर देख गांव का चूहा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने देखा टेबल पर कई तरह के खाद्य पदार्थ रखे थे। गांव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चखा। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि उन दोनों को बिल्ली की आवाज सुनाई दी। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। नहीं तो बिल्ली हमारा शिकार कर लेगी।' गांव का चूहा काफी डर गया था। थोड़े ही देर में बिल्ली वहां से चली गई और दोनों बाहर आ गए। शहर के चूहे ने कहा 'अब कोई डर नहीं मित्र, वो बिल्ली जा चुकी है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू किया। अभी गांव के चूहे ने ब्रेड खाना ही शुरू किया था कि दरवाजे पर एक लड़का कुत्ते के साथ अंदर आने लगा। गांव के चूहे ने पूछा। शहर के चूहे ने पहले बिल में छुपने को कहा। फिर चूहे को बताया कि वो कुत्ता घर के मालिक का है, जो हमेशा यहां रहता है। इस बार गांव का चूहा पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। शहर का चूहा गांव के चूहे से कुछ कहता, उससे पहले ही गांव के चूहे ने जाने के लिए इजाजत मांगी। गांव के चूहे ने कहा 'तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहां हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं रह सकता दोस्त।

7 अंतर खोजें

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष धनार्जन सुगम होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता अर्जित करेगा। पठन-पाठन में मन लगेगा। दूर यात्रा की योजना बन सकती है। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा।

वृषभ वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के व्यवहार से क्लेश हो सकता है। पुराना रोग उभर सकता है। दुःखद समाचार मिल सकता है, धैर्य रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

मिथुन शत्रु नतमस्तक होंगे। विवाद को बढ़ावा न दें। प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय ठीक चलेगा।

कर्क लेन-देन में सावधानी रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। परिवार में तनाव रह सकता है। शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।

सिंह रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

कन्या अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। किसी विवाद में उलझ सकते हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। जोखिम न उठाएं।

तुला बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा।

वृश्चिक नई आर्थिक नीति बनेगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबारी अनुबंधों में वृद्धि हो सकती है।

धनु बेचैनी रहेगी। चोट व रोग से बचें। काम का विरोध होगा। तनाव रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम अनुकूल होंगे। पूजा-पाठ में मन लगेगा। तीर्थयात्रा की योजना बनेगी।

मकर स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवाद से क्लेश संभव है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। अपेक्षित कार्यों में अप्रत्याशित बाधा आ सकती है। तनाव रहेगा।

कुम्भ कष्ट, भय, चिंता व बेचैनी का वातावरण बन सकता है। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी।

मीन धन प्राप्ति सुगम होगी। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। भूमि, भवन, दुकान व फैक्टरी आदि के खरीदने की योजना बनेगी। रोजगार में वृद्धि होगी।

हॉलीवुड | मन की बात

फिल्म इंडस्ट्री में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता : रानी मुखर्जी

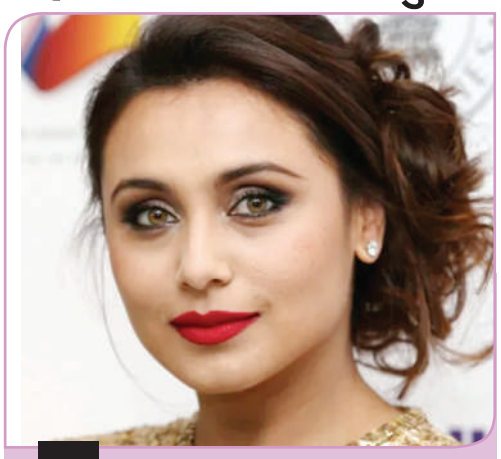

एआर रहमान ने पिछले दिनों इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव की बात कहकर इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसके बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंटी नजर आई। एक ओर जहां कई सेलेब्स ने रहमान को सपोर्ट किया, तो वहीं कई लोगों ने रहमान की इस को गलत बताते हुए इसका विरोध किया। अब अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भी एआर रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रानी मुखर्जी ने एआर रहमान के बॉलीवुड में सांप्रदायिक प्रभाव और काम पर पड़ने वाले असर के बारे में बात की। रानी ने कहा कि बॉलीवुड सबसे धर्मनिरपेक्ष जगह है और मैं इस पर पूरी तरह विश्वास करती हूं। यहां जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इंडस्ट्री में अपने 30 वर्षों में मैंने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। मुझे यह इंडस्ट्री बहुत पसंद है। इसने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूं। मैं यह दिल से कह रही हूं, यहां योग्यता मायने रखती है। आपका काम ही आपकी पहचान है और अंततः दर्शक जिस व्यक्ति से जुड़ते हैं, वही टिकता है और सफल होता है। मेरे लिए बॉलीवुड सबसे धर्मनिरपेक्ष और सबसे अद्भुत जगहों में से एक है। एआर रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क से बातचीत के दौरान कहा था, 'आजकल जो लोग रचनात्मक नहीं हैं, उनके पास फैसले लेने की शक्ति है। यह शायद एक सांप्रदायिक मुद्दा भी रहा हो, लेकिन मेरे सामने नहीं। मुझे कानाफूसी की तरह पता चला कि उन्होंने आपको बुक किया था, लेकिन संगीत कंपनी ने आगे बढ़कर अपने पांच संगीतकारों को काम पर रख लिया। मैंने कहा, वाह, बढ़िया है, अब मुझे आराम करने का समय मिल गया है, मैं अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिता सकता हूं।' इसके अलावा रहमान ने 'छावा' को विभाजनकारी फिल्म भी बताया था।

सलमान ने दबंग डायरेक्टर के खिलाफ किया मानहानि का केस

डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कई विवादित बयान दिए थे। उनके पिछले इंटरव्यूज खूब चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने सलमान की एक्टिंग से लेकर उनके बर्ताव पर सवाल खड़े किए। अभिनव ने एक्टर के कैरेक्टर पर भी गंभीर टिप्पणियां की थीं, जिसपर सलमान ने भी रिएक्ट किया था। अब इस मामले में कोर्ट की एंट्री हुई है, जिसमें सलमान और उनके परिवार को राहत मिली है।

शुक्रवार को मुंबई की एक कोर्ट ने अभिनव कश्यप, जो फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई हैं, उनको सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कोई बुरा या अपमानजनक कमेंट करने या नेगेटिविटी फैलाने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। सलमान ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। वो चाहते हैं कि ये रोक हमेशा के लिए लग जाए। उन्होंने अभिनव कश्यप से 9 करोड़ रुपये का नुकसान भरपाई की भी मांग की। साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगने की अपील की है।

अभिनव कश्यप ने सलमान के खिलाफ सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच 26 वीडियो इंटरव्यू और पॉडकास्ट जारी किए थे। कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि इन वीडियो में डायरेक्टर ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बहुत बुरे, झूठे और बेहद बदनामी वाले बयान दिए हैं। इस याचिका में अभिनव कश्यप के अलावा खुशबू हजारे और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी नामों को शामिल किया गया है।

याचिका के मुताबिक, डायरेक्टर ने सलमान और उनके परिवार के खिलाफ कई अभद्र टिप्पणियां की थीं। उन्होंने एक्टर के प्रोफेशनल करियर को लेकर भी झूठे दावे किए। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में खान परिवार को दोषी कहा। साथ ही उन्होंने सलमान की शक्ल, उम्र और निजी जिंदगी के बारे में बहुत गंदी-बदतमीजी वाली बातें कहीं। अभिनव कश्यप ने सलमान के पिता सलीम खान, और भाइयों अरबाज खान, सोहेल खान के खिलाफ भी बहुत अपमानजनक बातें बोली थीं।

सोशल मीडिया डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट!

आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके मुताबिक 2022 में मां बनने के बाद उनके अंदर कई बदलाव आए हैं। हाल ही में उन्होंने एक बातचीत में बताया कि वह अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं।

आलिया भट्ट ने बताया कि कई बार लगता है कि सोशल मीडिया से दूरी बना ली जाए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया जाए। एक अभिनेत्री होने के नाते अभिनय ही असली पहचान है। लगातार ऑनलाइन मौजूद रहने का दबाव कई बार थका देता है। आलिया के मुताबिक कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन करता है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जाएं। एक एक्ट्रेस के तौर पर जिया जाए।

आलिया भट्ट का वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। इसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल अहम भूमिकाओं में होंगे। इसके अलावा वो यशराज फिल्म्स की अल्फा का भी हिस्सा हैं, जिसमें शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी नजर आएंगे।

आलिया ने आगे कहा जब अपनी निजी जिंदगी को सबके सामने लाने की बात आती है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरी फोटो एल्बम राहा से भरी हुई है। मुझे अपनी तस्वीरें लेने के लिए सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आलिया भट्ट ने यह भी बताया कि मां बनने के बाद उनमें कई बदलाव हुए हैं।

आपको बता दें कि आलिया भट्ट ने कई वर्षों तक रणबीर कपूर को डेट करने के बाद अप्रैल 2022 में शादी की। उनकी पहली बच्ची राहा का जन्म नवंबर 2022 में हुआ।

अजब-गजब | ये है दुनिया का सबसे ठंडा शहर

यहां रहती है माइनस 50 डिग्री की सर्दी! फिर भी लोगों को महसूस नहीं होती ठंड

देश के कई हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ी हैं। दिसंबर-जनवरी आते ही भारत में लोग ठंड से कांपने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है, जहां ठंड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है? आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में बता रहे हैं, जहां तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह शहर रूस के सुदूर पूर्वी इलाके साइबेरिया में स्थित है। इसका नाम है याकुत्स्क।

इन दिनों यहां का तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस भीषण ठंड में भी यहां हजारों लोग सामान्य जीवन जीते हैं। याकुत्स्क में जनवरी का महीना सबसे ज्यादा ठंडा माना जाता है। यहां के लोग ठंड से बचने के लिए दो स्कार्फ, दो जोड़ी दस्ताने, मोटी टोपियां, हुड और भारी जैकेट्स पहनते हैं। कपड़े पहनने का तरीका ऐसा होता है, जैसे गोभी की परतें लपेट दी गई हों। यहां के लोगों का कहना हे कि वास्तव में शहर में ठंड महसूस नहीं होती है। यह भी

हो सकता है कि सिर्फ दिमाग में सोच कर रखा जाता है कि हम इसके लिए तैयार है, जिसके बाद लगने लगता है कि सबकुछ सामान्य है। यहां कई लोग फ्रोजन फिश बेचते हैं। ठंड से निपटने के लिए कोई विशेष रहस्य नहीं हैं। बस गर्म कपड़े पहनने चाहिए, जैसे परतों में गोभी लिपटी हुई होती है।

यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा ठंड में शरीर कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है, इसलिए ठंड ज्यादा महसूस नहीं होती। अगर आपने अच्छे गर्म कपड़े पहन रखे हों, तो शरीर धीरे-धीरे इस तापमान के साथ खुद को ढाल लेता है।

माइनस 20 डिग्री पर सांस लेते ही नाक के अंदर बर्फ जमने लगती है। माइनस 35 डिग्री पर त्वचा सुन्न पड़ जाती है और शीतदंश का खतरा बढ़ जाता है। वहीं माइनस 45 डिग्री पर चश्मा पहनना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह गालों से चिपक सकता है और उतारते वक्त त्वचा छिलने का डर रहता है। याकुत्स्क में लोग खुले बाजार में जमी हुई मछलियां बेचते हैं। इतनी ठंड में चीजें फ्रीज करने के लिए फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ती।

साइबेरिया में ही स्थित है दुनिया का सबसे ठंडा गांव ओयमयकोन। यहां का औसत तापमान माइनस 58 डिग्री सेल्सियस रहता है। साल 1933 में यहां का न्यूनतम तापमान माइनस 67.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं, जो खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहां नल से पानी लेना असंभव है। अगर पानी हवा में उछाल दिया जाए, तो वह जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाता है। गाड़ी चलाने से पहले उसे हीटेड गैराज में रखना जरूरी होता है।

इस गांव में कुत्ते हैं करोड़पति, हर साल ऐसे करते हैं करोड़ों की कमाई!

आपने इंसानों को करोड़पति बनते देखा होगा। गांवों में जमींदार होते हैं। इनके पास काफी जमीनें और पैसा होता है। लेकिन एक जगह ऐसे जमींदार भी हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये खास तरह के जमींदार हैं। ये खास तरह के जमींदार गुजरात के मेहसाणा स्थित पंचोट गांव में हैं। दरअसल ये जमींदार कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ते हैं। इस गांव के कुत्ते करोड़पति हैं। यह बिल्कुल सच है। मेहसाणा स्थित पंचोट गांव के कुत्ते हर साल करोड़ों कमाते हैं।

इस गांव में पिछले करीब एक दशक से जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मेहसाणा बाईपास बनने के बाद से यहां की जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यहां के कुत्तों को हुआ। दरअसल, 'मढ़नी पती कुतरिया ट्रस्ट' के पास गांव की 21 बीघा जमीन है। इस जमीन से होने वाली आय कुत्तों के नाम कर दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, बाईपास के पास होने की वजह से इस जमीन की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए प्रति बीघा है। वहीं इस ट्रस्ट के पास करीब 70 कुत्ते हैं। ऐसे में हर कुत्ते के हिस्से में लगभग एक-एक करोड़ रुपए आते हैं। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष छगनभाई पटेल का कहना है कि कुत्तों में ट्रस्ट का हिस्सा बांटने की परंपरा की जड़ गांव की सदियों पुरानी 'जीव दया' प्रथा से जन्मी है, जो आज तक चलती आ रही है। साथ ही उन्होंले बताया कि इस परंपरा की शुरुआत अमीर परिवारों ने की, जो दान दिए गए जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों से आरम्भ हुई थी। हालांकि, उस समय जमीनों की कीमत इतनी अधिक नहीं थी। बताया जाता है कि कई मामलों में तो लोगों ने टैक्स न चुका पाने की स्थिति में जमीन दान कर दी। इस जमीन का रख-रखाव पटेल किसानों के एक समूह ने करीब 70-80 साल पहले शुरू किया था, जो आज तक जारी है। ट्रस्ट के पास लगभग 70 साल पहले यह जमीन आई थी। समय के साथ जैसे-जैसे गांव का विकास होता गया जमीन के दाम बढ़ने लगे। इन दान की गई जमीनों से होने वाली कमाई का उपयोग गांव में मौजूद कुत्तों और अन्य जानवरों की देख-रेख करने के लिए किया जाता है।

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर कोहराम

» एनसीपी अध्यक्ष को लेकर भी बवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्र म घट रहे हैं, उन्होंने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्र वादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दिग्गज नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का आनन-फानन में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेना एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे चुका है। शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा और राकांपा के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी शिवसेना ने दावा किया कि राकांपा नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पीछे का 'सूत्रधार'भाजपा का नेतृत्व है। सुनेत्रा ने अपने पति अजित पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।

शिवसेना के मुखपत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेतृत्व और राकांपा नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल राकांपा के दोनों धड़ों का विलय नहीं चाहते हैं। पुणे जिले के

शिवसेना यूबीटी का सामना से तीखा प्रहार

किसकी इच्छा पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

बारामती में एक विमान दुर्घटना में राकांपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत के ठीक तीन दिन बाद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे तेजी से घटे इस घटनाक्र म को लेकर कुछ वर्गों से आलोचना भी हुई। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बारे में 'कोई जानकारी नहीं' थी। 'सामना' में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि न तो राकांपा (शप) अध्यक्ष शरद पवार, न ही उसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी थी। संपादकीय में यह भी कहा गया कि सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बारामती से मुंबई रवाना होने का जरा-सा भी संकेत नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे ने दावा किया, 'भाजपा नेतृत्व इस पूरी राजनीति का सूत्रधार है।'' उसने कहा, अजित पवार की मृत्यु के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में जटिलताएं बढ़ गई हैं। कई लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों का समाधान न हो।

फडणवीस की मेहरबानी पर निर्भर हैं सुनेत्रा और शिंदे

सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों का अस्तित्व फडणवीस की मेहरबानी पर निर्भर है। संपादकीय में कहा गया है कि सुनेत्रा पवार का उपमुख्यमंत्री पद महज दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी आशा व्यक्त की गयी है कि वह 'गूंगी गुड़िया' न होकर प्रभावी ढंग से काम करेंगी। इसमें दावा किया गया है कि राकांपा का 'सनातनी विचारधारा वाली' भाजपा के साथ गठबंधन है और सुनेत्रा पवार द्वारा अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों के पूरा होने से पहले ही शपथ लेना हिंदुत्व की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है।

एनसीपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनेगी अपना नया नेता: प्रफुल्ल पटेल

एनसीपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर जारी अटकलों पर अब विराम लग गया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से निराधार बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि वे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं। पटेल ने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से निराधार हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। पटेल ने कहा, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के बारे में चल रही कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी अपनी लीडरशिप चुनने के लिए अपनी स्थापित आंतरिक प्रक्रिया का पालन करेगी। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्था है। इतने बड़े फैसले हमारे सीनियर लीडरशिप और विधायकों से सलाह करके, हमारे समर्पित पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके, और हमारे सभी पार्टी सदस्यों की भावनाओं और सामूहिक इच्छा का सम्मान करके ही लिए जाएंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, हम इन मामलों में स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हैं।

सड़क सुरक्षामाह का समापन, लोगों को दिए टिप्स

» एआरटीओ ने प्रदुषण जांच केंद्र का किया निरीक्षण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गाजीपुर। जनपद लखनऊ में शनिवार को सड़क सुरक्षामाह का समापन हो गया है। इस अवसर पर एआरटीओ धनबीर यादव व पीटीओ लब कुमार सिंह टीम के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने बच्चों में ट्रफिक नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। एआरटीओ व पीटीओ ने जनपद में कई चालान किये। उन्होंने प्रदूषण केंद्रों की जांच भी की।

इसके तहत अधिकारियों ने वहां मौजूद रजिस्टर व मशीन चेक किया। हालांकि उन्हें कोई कमी नहीं मिली। इससे पहले गाजीपुर के एआरटीओ धनबीर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सुरक्षा माह को बहुत जिम्मेदारी के साथ सभी कर्मचारी शामिल रहे हैं। इसके तहत लोगों को ट्रैफिक संबंधी गुर बताए जा रहें हैं। गाजीपुर के एआरटीओ धनबीर यादव ने बताया कि इसमे हम आम जनता को एचएसआरपी लगे वाहन, व लोबीम हाईबीम,लेनों की जानकारी दे रहे हैं।

बजट में तमिलनाडु के लिए कुछ भी ठोस नहीं

» कनिमोझी ने कहा- केंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा लेकिन दुर्लभ खनिजों का खनन करना चाहता है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि विस चुनाव नजदीक होने के बावजूद तमिलनाडु को महत्वपूर्ण आवंटनों और घोषणाओं में नजरअंदाज किया गया है। बजट पर बोलते हुए कनिमोझी ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है। अधिकांश राज्यों ने 50 प्रतिशत धनराशि के आवंटन का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने केवल 41 प्रतिशत ही आवंटित किया है। यह सभी राज्यों के लिए बेहद निराशाजनक है और इस बजट में कुछ भी ठोस नहीं है।

कनिमोझी ने आगे कहा कि आगामी चुनावों के बावजूद यह बजट तमिलनाडु को कोई ठोस लाभ नहीं देता है और इसे राज्य के लिए निराशाजनक बजट बताया। कनिमोझी ने कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने तमिलनाडु के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया है। वे हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर वे तमिलनाडु से दुर्लभ खनिजों का खनन करना चाहते हैं। यह बेहद निराशाजनक बजट है।

बजट से केरल को बस निराशा मिली : वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय बजट 2026-2027 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे केरल के लिए घोर निराशा बताया और आरोप लगाया कि यह आम जनता के बजाय बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से केरल के लिए कोई विशेष घोषणा न होने पर सवाल उठाया, खासकर राज्य में एम्स की स्थापना के लंबे समय से लंबित वादे का। उन्होंने कहा कि केरल के लिए क्या घोषणा की गई है? केरल के लिए घोर निराशा। पिछले दस वर्षों से वे केरल को एम्स देने का वादा कर रहे हैं। इस बजट में केरल के लिए एम्स का कोई जिक्र नहीं है। वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह आम नागरिकों की चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं है। यह बड़े कॉरपोरेट घरानों का बजट है। बजट को सारहीन बताते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि लोग इस बजट का स्वागत कैसे कर सकते हैं? इसमें कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरह खोखला है। इससे पहले दिन में, वेणुगोपाल ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे एक दिशाहीन सरकार का बेजान, भावनाहीन बजट बताया, जो आम भारतीयों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है और उनके गृह राज्य केरल के लिए कुछ खास नहीं करता है।

काव्यामृत-3 की समीक्षा से गदगद हैं कवि शलभ

» आज का आनंद ने किया प्रकाशित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पुणे और मुंबई से एक साथ प्रकाशित महाराष्ट्र के 55 वर्ष से निरंतर हिंदी भाषियों की पहली पसंद दैनिक समाचार-पत्र आज का आनंद में ,जो प्रतिदिन लाखों पाठकों के हाथों में जाता है उसमें लखनऊ के कवि राजेश अरोरा शलभ की नवीनतम 21वीं पुस्तक गीता-काव्यामृत-3 (अध्याय 13-18) की समीक्षा की गई है। इसप शलभ ने कहा कि ये पढ़कर प्रसन्नता की अनुभूति हुई।

बता दें इस कृति का लोकार्पण विगत 1 दिसम्बर , विश्व गीता दिवस पर लखनऊ के उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में हुआ था। शलभ ने लोगों से अपील की है किसमीक्षा पढ़कर प्रतिक्रि या दें। उन्होनें पुस्तक की विस्तृत समीक्षा के प्रकाशन हेतु आज के आनंद टीम को आभार व्यक्त किया।

शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

» अंडर-19 विश्वकप से पाक बाहर

» भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 58 रनों से दी मात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बुलावायो। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हर विभाग में पछाड़ते हुए 58 रनों से करारी शिकस्त दी और शानदार अंदाज में सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। यह मुकाबला सिर्फ जीत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रणनीति और इरादों की पूरी तरह पोल खोलने वाला रहा।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम ने 252 रन बनाए थे और पाकिस्तान को ये लक्ष्य सेमीफाइनल में पहुंचने और अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए 33.3 ओवर में 253 रन का लक्ष्य हासिल करना था। लेकिन पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ऐसा नहीं कर सकी और 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर ही ऑलआउट हो गई। भारत के लिए इस मुकाबले में आयुष म्हात्रे और खिलान पटेल ने तीन-तीन विकेट झटके। भारत की इस धमाकेदार जीत के नायक रहे युवा ऑलराउंडर कनिष्क चौहान, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। निचले क्रम में 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 35 रन ठोककर उन्होंने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजी में 10 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर पाकिस्तान की रनगति पर ब्रेक लगा दिया। पिच से स्पिनरों को मदद मिलते ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। एक छोर से डॉट बॉल्स, दूसरे छोर से विकेट के साथ भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सांस तक नहीं लेने दी। विकेट गिरते गए और रन रुकते गए। आखिरकार पूरी पाकिस्तानी टीम 194 रन पर ढेर हो गई, और भारत ने 58 रनों की बड़ी जीत दर्ज की।

बहिष्कार की नौटंकी करने वाले पाक पर लगाम कसने की तैयारी!

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने रविवार को भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप का मुकाबला खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रीय टीम को सात फरवरी से होने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट में खेलने की मंजूरी दी है, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान बहिष्कार की नौटंकी कर रहा है, लेकिन उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बयान में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की कोई वजह नहीं बताई गई। आईसीसी ने पाक के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि इस बहिष्कार के परिणामस्वरूप दंडात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है जिसका वह स्वयं एक सदस्य और लाभार्थी है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर आईसीसी ने कहा कि वह पीसीबी से आधिकारिक संवाद की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन रचनात्मक भागीदारी का यह रुख किसी भी वैश्विक खेल प्रतियोगिता की मूल भावना के विपरीत है।

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास घेरा

» घर के बाहर किया प्रदर्शन पुलिस ने रोका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। इसी को लेकर अभ्यर्थी केशव मौर्य के घर के सामने धरने पर बैठे थे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाकर धरने पर बैठ गए।

पुलिस ने सभी को बस से धरनास्थल इको गार्डेन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, सरकार ने उसे जानबूझ कर लटका दिया। इससे मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार के पास पर्याप्त समय था, वह हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करके सबके साथ न्याय कर सकती थी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल व धनंजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया।

उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। लेकिन, सरकार इस प्रकरण में हीलाहवाली करती रही। पटेल ने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी कई बार केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था। तब उन्होंने त्वरित न्याय किए जाने की बात कही थी। हम अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी। लेकिन, उनकी बात को भी अधिकारियों ने नहीं माना। अब यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया।

हम पिछड़े दलित गरीब अभ्यर्थी अधिकारियों और सरकार के इस रवैया से काफी हताश और परेशान हैं। जो काम कुछ दिनों में हो सकता था, उसे इतना लंबा जानबूझकर टाल दिया गया है। केशव का त्वरित न्याय की टिप्पणी, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग साबित हुआ। त्वरित न्याय की कोई सीमा होती है यह नहीं की महीनों मामला लटक रहे।

आज देश में असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई : खरगे

» कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट को बताया दूरदर्शिता से दूर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।

उन्होंने आरोप लगाया कि असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है। एक पोस्ट में उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मेक इन इंडिया कहां है और दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13प्रतिशत पर अटकी हुई है।

गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को कोई राहत नहीं

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अधिक अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को कोई राहत प्रदान करती हैं। संघवाद को भारी नुकसान हुआ है। क्या गायब है और कहाँ मायने रखता है।विनिर्माण- कोई पुनरुद्धार रणनीति नहीं; 13प्रतिशत पर अटका हुआ है। मेक इन इंडिया कहाँ है? इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता की आलोचना की और वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।

मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे

खरगे ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं। बजट2026 भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। मिशन मोड अब चुनौती मार्ग बन गया है। सुधार एक्सप्रेस शायद ही किसी सुधार जंक्शन पर रुकती है। नतीजा कोई नीतिगत दूरदृष्टि नहीं, कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। हमारे अन्नदाता किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य पर संसद में हंगामा

» पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब पर मचा बवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन की परंपरा और नियमों का उल्लेख करते हुए राहुल को आगाह किया कि लोकसभा में ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। राहुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे।

राहुल गांधी सदन को गुमराह ना करें : राजनाथ

इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आपत्ति जताई और कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह ना करें। राहुल गांधी ने सदन में एक अप्रकाशित किताब के कोट्स का हवाला दिया, जो सदन के नियमों के खिलाफ है। जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका सोर्स भरोसेमंद है और इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित संस्मरणों के कोट्स शामिल हैं। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से नियमों का पालन करने की अपील की। ओम बिरला ने कहा कि नियमों और परंपरा से संसद चलना चाहिए।

आंध्र प्रदेश में बढ़ा सियासी बवाल वाईएसआरपी नेता का घर फूंका

» पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच वाईएसआरसीपी नेता जोगी रमेश के घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। यह घटना वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता अंबाती रामबाबू पर जानलेवा हमले के आरोप के एक दिन बाद सामने आई है।

स्थानीय समाचार चैनलों पर प्रसारित फुटेज के अनुसार, इब्राहिमपटनम में कई घंटों तक अराजक माहौल बना रहा, जहां दर्जनों लोग रमेश के घर में तोड़फोड़ करते और उसके कुछ हिस्सों में आग लगाते नजर आए। पश्चिम जोन के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) दुर्गा राव ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसीपी ने आगे कहा कि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया कि घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई, घरों में सामान क्षतिग्रस्त हो गया और परिसरों में तोड़फोड़ की गई। वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया कि प्रमुख बीसी नेता रमेश को जानबूझकर निशाना बनाया गया था और दावा किया कि यह घटना आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था के पूर्ण पतन को दर्शाती है। विपक्षी दल ने कहा कि दो दिनों के भीतर पूर्व मंत्रियों पर लगातार हमले विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक धमकियों का एक पैटर्न दर्शाते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया इसी बीच, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर हिंसा और अराजकता भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं पर हमले असहमति को दबा नहीं सकते।

पुणे के पोर्श हादसा मामले में सुप्रीम फैसला

» तीन आरोपियों को जमानत मिली

» सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय हो

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चर्चित पुणे पोर्श कार हादसा मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय होती है, क्योंकि वे अपने नाबालिग बच्चों पर सही नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा, नशे की समस्या अलग बात है, लेकिन बच्चों को कार की चाबियां और खुला पैसा देना ताकि वे ऐश कर सकें, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल-

इनके खून के सैंपल जांच में इस्तेमाल किए गए थे, जबकि वे कार में मौजूद दो नाबालिगों से जुड़े बताए गए। इससे पहले दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमर गायकवाड़ समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था और अब तीनों को जमानत दे दी गई है। इस मामले में ब्लड सैंपल बदलने के मामले में कुल 10 लोगों को जेल भेजा गया था, जिनमें नाबालिग के माता-पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावरे और श्रीहरी हालनोर, ससून अस्पताल का कर्मचारी अतुल घाटकांबले, और दो बिचौलिए शामिल हैं। पुणे शहर में 18-19 मई 2024 की दरम्यानी रात को करीब तीन करोड़ रुपये की पोर्श कार को तेज गति से दौड़ाने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक अपना संतुलन खोकर काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चली गई, जिससे उस पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था। जब विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद पुणे पुलिस के आग्रह पर जेजेबी ने आदेश बदला और नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा। हालांकि, जून 2024 में हाई कोर्ट ने नाबालिग की रिहाई का आदेश दे दिया।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय :- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।